

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

राजस्व निगरानी क०...../13

R-3249-III/13

1. इमरान फारुकी तनय श्री ई०आई०फारुकी
2. रिजवान फारुकी तनय श्री ई०आई०फारुकी
3. कहकशा फारुकी तनय श्री रिजवान फारुकी
4. सहला फारुकी तनय श्री इमरान फारुकी

सभी निवासी नजीराबाद तहसील रघु०नगर जिला सतना म०प्र०—निगराकारगणबनामशासन म०प्र०द्वारा हल्का पटवारी लौहरीय तहसील उचेहय जिला सतना—गैर निगराकारनियामी अक्टोवत घाय 50-म०प्र०भू०य०सं०-1959

विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सतना के
रा०प्र०क०-137/अपील/12-13 मे पारित आदेश
दिनांक 22.06.2013

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर
निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

निगराकारगणो द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदित आराजी के पूर्व मालिक स्वामी लल्ला/लक्ष्मी तनय भानूदत्त द्वारा उक्त आराजी जरिये रजि०विकय पत्र दिनांक 09.01.67 के आधार पर क्रय कर मौके से कब्जा दखल प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर अपने नाम नामान्तरण रा०प्र०क०-71अ51/70-71 में पारित आदेश दिनांक 17.11.71 के आधार पर प्रमाणित होने के बाद वह पूर्णतः मालिक स्वामी एवं अधिपत्यधारी होने के उपरान्त अपनी आवश्यकतानुसार उक्त आराजी निगराकारगणो को जरिये रजि०विकय पत्र दिनांक 02.08.95 को विक्रीत किया जाकर अपने सामान मौके से कब्जा दखल एवं अधिपत्य सौंप दिया गया। जिसमें निगराकारगणो द्वारा विकय पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तरण प्रमाणित कराये जाने के उपरान्त आराजी को पूर्णतः कृषि योग्य बनाया जाकर कृषि कार्य कर आबाद हुये। क्योंकि उक्त आराजी पूर्व से ही कृषि भूमि थी, किन्तु उक्त आराजी पर भूलवश लगान नियत न होने के कारण निगराकारगणो के पूर्व भूमिस्वामियों द्वारा नायब तहसीलदार अटरा के समक्ष प्रकरण क्रमांक-11अ74/2000-01 प्रस्तुत किया जाकर लगान निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिसमें विधिवत इशतहार का प्रकाशन होने पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा लगान निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी, जिसके आधार पर प्रकरण शिकायती के आधार पर कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष मूल प्रकरण सुनवाई

Conti.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक R3249-1/2013 जिला- मन्दा

इम्वाल कामकी विरुद्ध म० प्र० हालत

(1)	(2)	(3)
181218-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. शमेश यादव..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- मन्दा के प्रकरण क्रमांक 137/19/12/13..... में पारित आदेश दिनांक 22.6.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म० प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>